दिल्ली विश्वविद्यालय का दयाल सिंह कॉलेज बना वन्दे मातरम् का अखाड़ा

रवींद्र गोयल

आजकल दिल्ली विश्वविद्यालय के दयाल सिंह कॉलेज (सांध्य) में छुटभैय्ये संघी नेताओं द्वारा अपने तुच्छ स्वार्थों की पूर्ती हेतु सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का एक नया खेल खेला जा रहा है। इससे दिल्ली में उच्च शिक्षा सुविधाओं का कितना नुकसान होगा यह तो अभी नहीं कहा जा सकता पर यह तय है की दो उच्चशिक्षा संस्थान बर्बादी की राह पर तेजी से बड़ रहा है।

किस्सा मुक्तसर यूँ है:

दयाल सिंह कॉलेज (सांध्य) की शुरुआत 1959 के दशक में नौकरीपेशा लोगों को पढाई का एक मौका देने के उद्देश्य से हुई थी। बाद में यहाँ एक प्रात: कॉलेज की भी स्थापना हुई। 1978 में ये कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने मातहत ले लिया। 1986 में, (राजीव गांधी के शासन काल में) शिक्षा मंत्रालय का नाम बदल कर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया, और उच्च शिक्षा से सरकारी हाथ खींचने की नीति की शुरुआत हुई। नतीजे के तौर पर दिल्ली में उच्च शिक्षा की सुविधाओं में बढ़ोतरी पर रोक लगी। इसका एक नतीजा हुआ की नौकरीपेशा लोगों के लिए भी शिक्षा की सुविधाओं में कटौती हुई। सांध्य कॉलेज को दोपहर बाद चलने वाले कॉलेज में तब्दील किया गया। यानि अब नौकरीपेशा लोग नहीं इन कॉलेजों में भी पूर्ण कालिक छात्र ही पढ़ पायेंगे। अपने अटपटे समय के चलते (दोपहर से शाम तक) ये कॉलेज पूर्णकालिक छात्र की दूसरे दर्जे की पसंद ही थे। और यह अध्यापकों के लिए भी उतने आकर्षक नहीं रहे जितने सांध्य कॉलेज होते थे। सांध्य कॉलेज में तो थोड़े समय के लिए ही जाना होता था वो भी शाम को ही। यह सही हैं की शाम बर्बाद होती थी पर पूरा दिन तो अपने पास था.लेकिन दोपहर का कॉलेज हो जाने के बाद तो पूरा दिन ही नौकरी के नाम हो गया। जब उनके अन्य शिक्षक साथी खाली होते तभी सांध्य कॉलेज के शिक्षकों का नौकरी का समय हो जाता। इस लिए छात्र और शिक्षकों दोनों की दिली इच्छा यह बनना स्वाभाविक है की उनके दोपहर के कॉलेज प्रात: कॉलेजों में तब्दील हो जाएँ। ऐसे में बहुत महत्वाकांक्षी प्रिंसिपल या भ्रष्ट गवर्निंग बॉडी पदाधिकारी जहाँ भी सांध्य कॉलेजों में आये वहां इस मांग का जोर पकड़ना लाजमी थ। क्योंकि प्रात: कॉलेज का अर्थ होता नयी बिल्डिंग में कमिशन का जुगाड़ और कॉलेज में अपने प्रिय बंधुओं को ज्यादा नौकरी लगवाने की सम्भावना।

लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। जहाँ इन कॉलेजों की प्रात: कॉलेजों में तब्दील हो जाने की आकाँक्षा वाजिब है वहीँ यह आवश्यक है कि उसके लिए नई जमीन और नए आधारभूत सुविधाओं का इंतजाम किया जाय। पुराने प्रात: कॉलेज के ढाँचे में ही नए कॉलेज को ठूंस देने से काम नहीं चलेगा एक कॉलेज की आधारभूत सुविधाओं में दो पूर्णकालिक कॉलेज नहीं चल सकते। संध्या कॉलेज तो फिर भी चल जाते थे क्योंकि उस समय प्रात: कॉलेज के छात्र अपने घर चले गए होते थे। और आधार भूत सुविधाओं को संध्या के छात्र इस्तेमाल कर सकते थे।

पर ये सरोकार सांध्य कॉलेज के महत्वाकांक्षी प्रिंसिपल या भ्रष्ट गवर्निंग बॉडी पदाधिकारीयों का कम ही होता है। इनकी रूचि ज्यादा बढ़ी जागीर खड़ी करने और उसमें भ्रष्टाचार के मौके तलाशना होता है। और यही वर्तमान में दयालसिंह कॉलेज सांध्य के वन्दे मातरम् संस्करण की जड़ में है। सांध्य कॉलेज के नए संघी प्रिंसिपल पवन कुमार शर्मा और गवर्निंग बॉडी अध्यक्ष अमिताभ सिन्हा के आते ही इस मंसूबे को पंख लग गए। आनन् फानन में विश्वविद्यालय प्रशासन ने मंजूरी दे दी। और क्यों न मिलती जब दिल्ली विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण शिक्षक नेता जो इसी कॉलेज से हैं इस फैसले के समर्थक हों। और कॉलेज को प्रात: कॉलेज बनाने की तैयारी

लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए. जहाँ इन कॉलेजों की प्रात: कॉलेजों में तब्दील हो जाने की आकाँक्षा वाजिब है वहीँ यह आवश्यक है की उसके लिए नइ जमीन और नए आधारभूत सुविधाओं का इंतजाम किया जाय. पुराने प्रात: कॉलेज के ढाँचे में ही नए कॉलेज को ठूंस देने से काम नहीं चलेगा. एक कॉलेज की आधारभूत सुविधाओं में दो पूर्णकालिक कॉलेज नहीं चल सकते. संध्या कॉलेज तो फिर भी चल जाते थे क्योंकि उस समय प्रात: कॉलेज के छात्र अपने घर चले गए होते थे. और आधार भूत सुविधाओं को संध्या के छात्र इस्तेमाल कर सकते थे.

शुरू हो गयी। ठेके पर निर्माण ओर कमीशन के हिसाब लगाये जाने लगे। गवर्निंग बॉडी अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के वकील अमिताभ सिन्हा जी, ने तो कॉलेज में अपना दफ्तर ही खोल लिया है।

बस एक ही पेच फँस रहा था. पहले ही कॉलेज की कुछ जमीन मेट्रो रेल कार्यक्रम में चली गयी है। प्रात: कॉलेज बुनियादी ढांचे के आभाव में कराहा रहा है। वर्तमान में 6000 छात्रों की कक्षाओं के लिए कमरे नहीं हैं , शिक्षकों के बैठने के लिए स्थान नहीं है। ऐसे में प्रात: कॉलेज के छात्र, शिक्षक और कर्मचारी प्रात: कॉलेज के ढाँचे में ही नए कॉलेज को ठूंस देने की कवायद का मुखर विरोध कर रहे हैं। लेकिन सरकार या यूनिवर्सिटी नए कॉलेज के लिए जमीन देने की बजाये लम्बरूप संरचना (vertical structure) का विज्ञान समझा रही है. ऐसे में यदि दयाल सिंह कॉलेज (सांध्य) को प्रात: कॉलेज बनाना है, बडी जागीर खड़ी करने और उसमें भ्रष्टाचार की सम्भावना को असलियत में बदलना है तो कोई राम बाण चलाना ही पड़ता जिससे इस विरोध से निपटा जा सकता। गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष और प्रिंसिपल साहब ने अपने लगुओं भगुओं के साथ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और राष्ट्रवादी अफीम खिलाने की तैयारी की। इसी 17 नवम्बर की गवर्निंग बॉडी की मीटिंग में नए कॉलेज का नाम वन्देमातरम महाविद्यालय तय कर लिया गया। इस निर्णय का एक सदस्य को छोड़ कर सभी ग्यारह सदस्यों ने समर्थन किया। ध्यान रहे की इस फैसले से पहले जब यह अनुमान था की कॉलेज के भीतर संघी सूरमा विरोध को निपट लेंगे तो मदन मोहन मालवीय का नाम पर कॉलेज का नाम रखने की पेशकश हुई थी।

अपनी समझ से फैसला तो लाजवाब किया था। संघी सूरमाओं की फौज भी इस सवाल पर राष्ट्रवाद फैलाने की मुहिम में शामिल हो गयीं। बस एक तो कानूनी चूक हो गयी। नियमानुसार गवर्निंग बॉडी को 4 नामों की सूची विश्वविद्यालय प्रशासन को भेजनी थी पर एक ही नाम भेज कर इन मूर्खों ने एक त्रुटि कर दी है। ये अलग बात है की यह गवर्निंग बॉडी कानून की कम चिंता ही करती है। ध्यान रहे की प्रात: कॉलेज के शिक्षक केदार मंडल को इस गवर्निंग बॉडी ने विश्वद्यालय के द्वारा स्वीकृति के बिना ही सस्पेंड कर दिया है। यह विश्वविद्यालय के कानून के खिलाफ है पर जब सरकार अपनी हो तो कानून को कौन पूछता है। गनीमत है कि न्यायमूर्ति बृजगोपाल हरकिशन लोया की तरह रास्ते से विरोधियों को किनारे नहीं करा दिया गया।

दूसरे इन भगवा धारियों को यह भी अंदाजा नहीं था इस फैसले से सिख/ पंजाब अस्मिता भी आहात होगी। वो दयाल सिंह ट्रस्ट का दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ 1978 में हुए समझौते का हवाला देते हुए इस फैसले के औचित्य पर सवाल उठा रहे हैं। उनका यह भी तर्क है की जब लाहौर में चल रहे दयाल सिंह कॉलेज का नाम आज तक नहीं बदला गया तो फिर हिंदुस्तान में नाम क्यों बदला जाये। कुछ सिख नेताओं ने तो उपरोक्त समझौते का हवाला देते हुए दयाल सिंह कॉलेज के गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन और दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल के विरुद्ध पुलिस कंप्लेंट भी करा दी है। अभी तो गवर्निंग बॉडी अध्यक्ष सिन्हा जी दहाड़ रहें हैं की वो नाम के सवाल पर कोई परिवर्तन नहीं करने वाले पर ज्यादा सम्भावना है कि इस मामले में भाई विकास नारायण राय का आकलन सही ही साबित हो। कुछ दिन पहले उन्होंने लिखा था- दयाल सिंह कॉलेज का नया नामकरण भी गजेंद्र चौहान थूको-चाटो श्रृंखला की कड़ी ही साबित होगा।

वैसे आलामा इकबाल ने बहुत पहले ही कहा था

बर्बाद गुलिस्ताँ करने को एक ही उल्लू काफी है

हर शाख पे उल्लू बैठे हैं अंजामे गुलिस्ताँ क्या होगा

गतांक की चीर-फ़ाड़

डा. जुगल किशोर गुप्ता

मास्टरों की कमी दूर करने का नायाब तरीका व नोटबंदी का गुणगान

मज़दूर मोर्चा के 16-30 नवम्बर 2017 के अंक में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय व स्थानीय मुद्दों पर अनेक महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित हुए हैं। बिल्डरों की तानाशाही, मनमानी व लूट से पीड़ित 'फ्लैट मालिकों की परेशानियों का लेख' फ्लैट मालिकों की हैसियत किराएदारों सी बना रखी है बिल्डरों ने-केएलजे ग्रीन्स वासियों ने बजाया विद्रोह का बिगुल, प्रशासन उदासीन' में विस्तृत वर्णन किया गया है। हरियाणा विद्युत विभाग ने अपनी नालायकी व कमजोरी से बचने के लिये सोसायटी को एक मीटर लेने के लिये मजबूर किया है और इसी मीटर से बिजली का बिल वसूल किया जाता है। फ्लैटों से वसूली बिल्डरों द्वारा मनमर्जी दर से की जाती है। फ्लैटों की व्यवस्था बनाए रखने के लिये सभी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को हरियाणा अपार्टमेन्ट एक्ट के अन्तर्गत अपनी-अपनी प्रबंध समिति का गठन करना होता है, परंतु कोई भी बिल्डर इस अधिनियम की परवाह नहीं करता। प्रशासन व हूडा द्वारा इस अधिनियम के उल्लंघन की ओर ध्यान न देने के कारण बिल्डरों की धींगामस्ती चल रही है।

भाजपा की केन्द्रीय व हरियाणा सरकार ने राज्य में शिक्षा के स्तर व व्यवस्था में सुधार को नज़रंदाज कर रखा है। सरकारी शिक्षण संस्थाओं में न तो पर्याप्त भवन व सुविधाएं हैं और ना पर्याप्त शिक्षक हैं। जब किसी शिक्षण संस्था में शिक्षक ही नहीं होंगे और पढाने की पूरी व्यवस्था नहीं होगी तो उस सरकारी शिक्षण संस्था में विद्यार्थी क्यों आएंगे। शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिये शिक्षकों की नियुक्ति करने की बजाए हरियाणा सरकार ने कम विद्यार्थियों वाले स्कूलों को ही बंद करने का निर्णय कर लिया जिसका 'मास्टरों की कमी दूर करने का नायाब तरीका: स्कूलों को ही बंद करो' व 'गंदगी के ढेर पर पढने को मजबूर हैं नौनिहाल' लेखों में उपयुक्त विवेचन किया गया है। इस निर्णय से सरकार का मकसद साफ़ है कि निजी शिक्षण संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाये जो विद्यार्थियों से मोटी फीस वसूलते हैं। इसमें नेताओं व निजी शिक्षण संस्थाओं के मालिकों के बीच गठजोड़ जाहिर होता है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अपने आपको सिद्धांतवादी, भ्रष्टाचार विरोधी, राष्ट्रवादी आदि का दावा करते हुए अन्य पार्टियों से अलग मानती है, परंतु जब अन्य पार्टी के नेताओं जैसे सुखराम, मुकुल रॉय आदि पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए तथा इस मुद्दे पर संसद बाधित की गई उनको खुले दिल से स्वागत करते हुए भाजपा में शामिल किया गया जिसका लेख 'राष्ट्रनिर्माण का यह एक अजीब नुस्खा है, सुखराम और मुकुल रॉय का भाजपा में शामिल होना ' में पूरा पर्दाफ़ाश किया गया है। हिमाचल प्रदेश व गुजरात विधानसभा चुनावों के दौरान जो कांग्रेसी नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए उनको तुरंत भाजपा का उम्मीदवार भी बना दिया गया।

आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव के परिदृश्य में भाजपा व कांग्रेस की स्थिति, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गुजरात मॉडल की वास्तविकता, तथाकथित विकास, मोदीजी द्वारा दिखाए गए अच्छे दिन के स्वप्न, काले धन की वापसी तथा प्रत्येक के बैंक खाते में 15 लाख रुपये जमा करने का सपना, नोटबंदी से अर्थ व्यवस्था का चरमराना, जीएसटी लागू करने के कुप्रभाव आदि का लेख 'अच्छे दिन हुए पूरे, गुजरात में नहीं चलेगा मोदी का जादू' में सटीक विश्लेषण किया गया है। मोदी की गुजरात में पकड़ कमजोर हो रही है और मोदी व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को जनता के प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसलिये मोदी व शाह ने 50 केन्द्रीय मंत्री, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री और अन्य बड़े नेताओं व संघ के वरिष्ठ प्रचारकों व कार्यकर्ताओं को वहां तैनात कर दिये हैं।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को व्यापम घोटाले में सीबीआई द्वारा बरी किए जाने पर 'जिसका तोता उसकी भैंस', नत्थूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या किए जाने पर अग्रणी हिन्दू राष्ट्र पत्रिका में छपे कार्टून जिसमें वी. डी. सावरकर तथा श्यामा प्रसाद मुखर्जी को राम व लक्ष्मण के रूप में तथा रावण के रूप में सरदार पटेल, राजगोपालाचारी, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, जवाहर लाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोहम्मद अलि, जिन्नाह, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, दादा भाई नौरोजी आदि के रूप में दिखाने व अमित शाह के बेटे जय शाह पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप पर भाजपा नेताओं व मंत्रियों द्वारा जय शाह को बचाने के प्रयास पर '' 'जय' को बचाना ज्यादा जरूरी है' तथा मोदी द्वारा लागू की गई नोटबंदी के एक वर्ष पूरा होने पर नोटबंदी से जनता की परेशानियों पर 'प्रथम नोटबंदी वर्षगांठ' कार्टुन द्वारा संघ व मोदी सरकार की नीतियों पर उचित व्यंग्य किया गया है।

कविता 'ऐसा भी क्या झूठा अहंकार जी' में मोदी जी द्वारा लागू की गई नोटबंदी के कारण आम लोगों की दुर्दशा व अनेक लोगों की मृत्यु होने पर भी मोदी जी द्वारा अहंकारवश इसे काले धन की समाप्ति के रूप में मनाए जाने पर सटीक व्यंग्य किया गया है। संघ व हिंदुत्ववादी लोग केवल संघ से सम्बन्धित व्यक्ति को ही हिंदू मानते हैं।

अन्य किसी को नहीं जिसको कविता 'महानतम हिन्दू' में स्पष्ट किया गया है। स्मॉग व पर्यावरण के नाम पर सरकार, न्यायालय, विभिन्न आयोग, मीडिया आदि द्वारा मचाए गए शोर तथा आम लोगों की स्थिति को नज़रंदाज किए जाने पर कविता 'लेकिन इस बार' में उचित व्यंग्य किया गया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरदार पटेल को महामंडित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, परंतु सरदार पटेल द्वारा आरएसएस के प्रति प्रकट किये गये विचारों को कभी प्रचारित नहीं करते और मीडिया भी इस बारे में चुप्पी साधे हुए हैं। सरदार पटेल द्वारा 11 सितम्बर 1948 को संघ प्रमुख गोलवलकर को लिखे पत्र तथा इतिहासकार रामचंद्र गुहा द्वारा महात्मा गांधी पर लिखी पुस्तक में वर्णित पटेल के संघ के बारे में विचारों को लेख 'राम से जय श्री राम तक... सरदार पटेल का आरएसएस के सरसंघचालक गोलवलकर को लिखा खत' प्रकाशित करके पाठकों को जागरूक करने का कार्य किया है।

गांधीजी की हत्या के बाद सरदार पटेल द्वारा 1948 में आरएसएस के प्रति प्रकट किये गए विचार आज भी प्रासांगिक है। कट्टर हिन्दुत्ववादी लोग अब भी कहते हैं कि मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकाल देना चाहिये। इसके अलावा संघ व भाजपा के लोग सभी मर्यादाएं ताक पर रखकर कांग्रेस पर हमला करते हैं और देश में अस्थिरता का माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं तथा उनके भाषणों में साम्प्रदायिकता का जहर भरा होता है।

अब पाठकों का कर्त्तव्य बनता है कि वे संघ के प्रति सरदार पटेल के विचारों को आम लोगों में प्रचारित व प्रसारित करें।